शहरी विकास विभाग

ऑउटकम बजट

वित्तीय (वर्ष 2024–25)

आउटकम बजट 2024–25
शहरी विकास विभाग
विभाग के अंतर्गत प्रस्तावित एस०डी०जी० : एस०डी०जी०–6 व 11

धनराशि लाख रु0 में

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	**प्रस्तावित आउट ले**		01–04–2023 की स्थिति (भौतिक)	31–03–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2024–25	आउटकम हेतु संम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
	राज्य सेक्टर								
1	अधिष्ठान व्यय	शहरी विकास निदेशालय कार्यालय अधिष्ठान	608.15	-	निदेशालय के अधिकारियों हेतु का वेतन भुगतान तथा कार्यालय सम्बन्धी अन्य व्यय	निदेशालय के कार्मिकों को वेतन भुगतान तथा कार्यालय सम्बन्धी व्यय	निदेशालय के कार्मिकों को वेतन भुगतान तथा कार्यालय सम्बन्धी व्यय	जन कल्याण कारी योजनाओं का संचालन तथा अनुश्रवण तथा नागरिको सुविधा प्रदान करना	2024–25
2	नगरीय अवस्थापना सुविधाओं का विकास	इस परियोजना का उद्देश्य स्थानीय निकायो की सीमान्तर्गत मूल–भूत नागरिक सुविधाये यथा–ड्रैनेज व्यवस्था, सड़क, गलियों, नालियों का निर्माण/सुधार विषयक परियोजनाए आदि हेतु नगर निकायों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।	--	5000.00	08 निकायों में अवस्थापना विकास जैसे नाला, नालियों, खडंजा, सुरक्षा दीवार, पार्किंग आदि का निर्माण।	45 निकायों में अवस्थापना विकास जैसे नाला, नालियों, खडंजा, सुरक्षा दीवार, पार्किंग आदि का निर्माण।	नगरीय निकायो में अवस्थापना विकास जैसे नाला, नालियों, खडंजा, सुरक्षा दीवार, पार्किंग आदि का निर्माण।	नगरीय अवस्थापना में विकास किया जायेगा। जिससे नगरीय क्षेत्रों में खराब नाले सड़को ड्रेनेज तथा निकाय क्षेत्र के अन्तर्गत पार्किंग व्यवस्था सुदृढ़ हो जायेगी।	2024–25
3	आवारा श्वान पशु बध्याकरण	आवारा निराश्रित श्वानवंशीय पशुओं की जनसंख्या नियंत्रण हेतु आवारा श्वानवंशीय बंध्याकरण कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके द्वारा ए0बी0सी0 कैम्पस (Animal Birth Control) की स्थापना की गयी है।	200.00	100.00	नगर निगम, देहरादून, हल्द्वानी, काशीपुर रूद्रपुर हरिद्वार नगर पालिका परिषद, मंसूरी एवं नैनीताल, पिथौरागढ में ए0बी0सी0 कैम्पस की स्थापना व संचालन। नगर निकाय देहरादून, नैनीताल ,मसूरी में 64795 श्वान पशुओं की बाध्यकरण शल्य चिकित्सा पूर्ण कर ली गई है	➢ नैनीताल, मसूरी, देहरादून हल्द्वानी पिथौरागढ, अल्मोडा, हर्बटपुर, विकासनगर, सेलाकुई, डोईवाला, भीमताल, भवाली में बध्याकरण का संचालन किया जा रहा है। ➢ वर्तमान तक कुल 75000 पशुओं का बाध्यकरण शल्य चिकित्सा पूर्ण। ➢ रूद्रपुर, रूड़की, काशीपुर अल्मोडा में ए0बी0सी0 कैम्पस का निर्माण कार्य प्रगति पर है।	➢ रूद्रपुर, रूड़की, अल्मोडा में ए0बी0सी0 कैम्पस का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। ➢ आवारा पशुओं का बाध्य चिकित्सा की जायेगी।	ए0बी0सी0 कैम्पस की स्थापना के उपरान्त निकाय क्षेत्र में आवारा घूम रहे ष्वान पशुओं की जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण सम्भव हो सकेगा।	2024–25

4	(UA-URIF) उत्तरांखण्ड शहरी स्थानीय निकाय सुधार प्रोत्साहन निधि	योजनान्तर्गत उत्कृष्ठ नगर निकायो को प्रोत्साहन स्वरूप प्रतिवर्ष पुरूस्कृत किया जाएगा, जिनके द्वारा कूड़ा एकत्रीकरण, पृथक्कीकरण, जैविक अपशिष्ट का उपचार, अजैविक अपशिष्ट का पुनर्चक्रीकरण एवं पुर्नउपयोग तथा शेष बचे अपशिष्ट का वैज्ञानिक भू–भरण करके निकाय क्षेत्र को स्वच्छ रखने का प्रयास करेगें।	100.00	–	स्वच्छ सर्वोक्षण 2023–24 में श्रेष्ठतम 09 निकायों की घोषणा होना प्रस्तावित है।	स्वच्छ सर्वोक्षण 2023–24 में श्रेष्ठतम 09 निकायों की घोषणा होना प्रस्तावित है।	शहरी स्थानीय निकायों को अभिनव कार्यों के लिए प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कृत किया गया ताकि उनके निकाय क्षेत्र में बेहतर काम करने का प्रयास कर सकें।	शहरी स्थानीय निकायों को अभिनव कार्यों के लिए प्रोत्साहन स्वरूप पुरस्कृत	2024–25
5	पार्को की स्थापना	राज्य में स्थित नगरों को सुन्दर बनाने के दृष्टिगत समस्त नगर निकायों को एक बार पार्को के निर्माण तथा वर्तमान में स्थित पार्को को सुदृढ़ीकरण किया जाना ।	500.00	––	नगर निकाय दिनेशपुर तथा कर्णप्रयाग में 02 पार्क का निर्माण	20 नगर निकायों में ओपन जिम एवं पार्क निर्माण अल्मोडा, लम्बगॉव कपकोट गरुड, पुरोला आदि निकायों की स्वीकृति मिलनी प्रस्तावित है।	30 नगर निकायों में ओपन जिम एवं पार्क का निर्माण/ सौन्दर्यकरण कराया जायेगा ।	नगरों को सुन्दर बनाने एवं नगर निकायों में एक बार पार्को के निर्माण तथा वर्तमान में स्थित पार्को का सुदृढ़ीकरण।	2024–25
6	सड़क पर रेड़ी, फेरी, भिक्षावृत्ति, कूड़ा बिनने वाले सपेरा आदि को सहायता	राज्य सरकार द्वारा फेरी नीति का विख्यापन किया गया है, जिसके अनुसार नगर निकायो में फेरी एवं रेडी लगाने वाले वेडरों का सर्वेक्षण कराकर उन्हें एक निश्चित पर रेडी फेरी लगाने हेतु स्थान उपलब्ध कराया जायेगा ।	10.00	––	धनराशि अवमुक्त नहीं की गई	धनराशि अवमुक्त नहीं की गई।	नगर निकायो में फेरी एवं रेडी लगाने वाले वेडरों को एक निश्चित पर रेडी फेरी लगाने हेतु स्थान उपलब्ध कराया जायेगा	फेरी एवं रेडी लगाने वाले वेडरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदात करते हुये रोजगार में संवर्द्धन।	2024–25
7	रैन बसेरो का निर्माण	इस योजनार्न्तगत नगर निकायो में आश्रयहीन लोगों के लिए रैन बसेरों का निर्माण किया जाना	50.00	100.00	वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 में 03 निकायों क्रमषः कोटद्वार, अल्मोड़ा तथा हरिद्वार में निर्माण कार्य प्रगति पर है।	03 निकायों कोटद्वार, अल्मोड़ा तथा हरिद्वार में निर्माण कार्य पूर्ण किये जायेगें।	08 नगर निकाय ऋषिकेष, गरूड़ कपकोट तथा बड़कोट में आश्रयहीन लोगों को रैनबसेरा प्रस्तावित है।	शहरी क्षेत्रों में आश्रयहीन गरीब लोगों को रात्रि विश्राम, ठहरने हेतु स्थान उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें शौचालय, बिस्तर, पानी आदि की निःशुल्क व्यवस्था होती है।	2024–25
8	सफाई कर्मचारियों हेतु पारितोषिक योजना	नगर निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के कार्य की विषमता को दृष्टिगत रखते हुए उनको पारितोषिक इस योजना के अन्तर्गत उपलब्ध कराया जाना है	20.00	--	निदेशालय के पत्र संख्या–3952, दिनांक 06–01–2024 द्वारा नगर निकायों को उनकी श्रेणी के आधार पर उक्त धनराशि अवमुक्त किए जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित है।	समस्त निकायों में 2000 सफाई कर्मचारियों को पुरूष्कृत किए जाने का प्रस्ताव है।	नगर निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को पारितोषिक	नगर निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को पारितोषिक तथा सामाजिक सुरक्षा। ताकि वे बेहतर काम करने का प्रयास कर सकें।	2024–25

9	सफाई कर्मचारियों हेतु स्वास्थ्य आरोहण योजना	नगर निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य के हितों की रक्षा के दृष्टिगत ये योजना प्रारम्भ की गई है	50.00	-	निदेशालय के पत्र संख्या–3369, दिनांक 06–12–2023 द्वारा उक्त धनरारिश को अवमुक्त किए जाने का प्रस्ताव शासन को प्रेषित है।	समस्त निकायो में सफाई कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण व स्वच्छता सामग्री उपलब्ध कराए जाने का प्रस्ताव है।	नगर निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य के हितों की रक्षा करना।	नगर निकायों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य के हितों की रक्षा। ताकि वे बेहतर काम करने का प्रयास कर सकें।	2024–25
10	हाईटेक शौचालयों का निर्माण	नगर निकायों में पर्यटकों की सुविधा हेतु आधुनिक शौचालयो का निर्माण योजना प्रारम्भ की गई। इससे पर्यटकों को सुविधा प्राप्त होगी ।	-	200.00	नगर पंचायत, पोखरी को रू0 6.744 लाख की धनराशि स्वीकृत हुआ है।	नगर निकाय अल्मोड़ा, नौगांव, काशीपुर, भवाली, लम्बगांव, कपकोट तथा गरूड़ में निर्मित कराये जायेगे।	20 नगर निकायों में पर्यटकों तथा आम जनता की सुविधा हेतु स्वच्छ शौचालय, बाथरूम की व्यवस्था होगी । साथ ही जिला मुख्यालय के शहरों में नये हाईटेक शौचालय निर्माण कराये जायेगे।	नगर निकायों में पर्यटकों तथा आम जनता की सुविधा हेतु स्वच्छ शौचालय, बाथरूम की व्यवस्था की गयी है	2024–25
11	निदेशालय भवन नि0	शहरी विकास विभाग के निदेशालय कार्यालय हेतु भवन उपलब्ध कराना	-	0.01	निदेशालय का भवन नही है	निदेशालय भवन निर्माण का आगणन रू0 13.00 करोड गठित है।	शहरी विकास निदेशालय के लिए कार्यालय भवन का निर्माण	जनसुविधाओं के दृष्टिगत निदेशालय भवन का निर्माण एवं निदशालय में कार्मिकों की संख्या में बढोत्तरी के दृष्टिगत आवश्यकता हेतु	2024–25
12	नगरीय पर्यावरण परिषद	नगरीय पर्यावरण सरक्षण परिषद के मा0 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का मानदेय आदि भुगतान	3.10	-	नगरीय पर्यावरण परिषद का गठन प्रस्तावित	नगरीय पर्यावरण परिषद का गठन प्रस्तावित	नगरीय पर्यावरण सरक्षण परिषद के मा0 अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का मानदेय आदि भुगतान	जन कल्याणकारी योजनाओं का संचालन तथा अनुश्रवण तथा नागरिको सुविधा प्रदान करना	2024–25
13	आवारा पशुओं का आश्रय निर्माण/ संचालन	नगर निकायो में अवारा पशुओं के सरंक्षण हेतु गौसदन का निर्माण/ संचालन	500.00	1500.00	नगर निकाय, लक्सर, टिहरी, देवप्रयाग, गजा, कीर्तिनगर, चमियाला, घनसाली, पीपलकोटी, पोखरी को कुल रू0–223.71 लाख की धनराशि निर्गत की गयी है।	09 निकायों में अवारा पशुओं के सरक्षण हेतु गौसदन का निर्माण व संचालन किया जाना प्रस्तावित।	वर्ष 2024–25 में नई योजना प्रस्तावित की गयी है। 12 निकायों में अवारा पशुओं के सरक्षण हेतु गौसदन का निर्माण व संचालन किया जायेगा।	नगर निकायों में अवारा पशुओं से जनता व फसलों को हानि से सुरक्षा मिलेगी साथ ही सड़को पर आवागमन सुलभ होगा	2024–25

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले/बजट		01–04–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक स्थिति)	31–03–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2024–25	आउटकम हेतु संभावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
14	((बाह्य सहायतित) नगरीय अवस्थापना का सुदृढ़ीकरण **(UIRUDP) Loan No 4148-IND**	ADB के सहयोग से 02षहरों (देहरादून एवं नैनीताल) में नगरीय अवस्थापना जैसे सीवरेज, वॉटर सप्लाई तथा स्लम का सुदृढ़ीकरण व विकास किया जायेगा। ● वाटर सप्लाई – 136 कि.मी. ● सीवर – 260 कि.मी. ● एस0टी0पी0– 03 नग (46 एम0एल0डी0) ● बरसाती जल प्रबंधन – 117 कि.मी. ● सीवर कनैक्शन – 17410 नग	2500.00	15000.00	भारत सरकार के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य में ADB के सहयोग से 02 ष्षहरों (देहरादून एवं नैनीताल) में नगरीय अवस्थापना जैसे सीवरेज, वॉटर सप्लाई का सुदृढ़ीकरण व विकासकार्य प्रगति पर है। ● वाटर सप्लाई –74 कि.मी. ● सीवर –185 कि.मी. ● एस0टी0पी0–कार्य प्रगति पर है। ● सीवर कनैक्शन–16385 नग। DEA भारत सरकार, ADB एवं शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा त्रिपक्षीय अनुबंध दिनांक 07.12.2021 को हस्ताक्षरित किया जा चुका है। देहरादून एवं नैनीताल नगर में 06 सब प्रोजेक्ट्स हेतु पेयजल, सीवरेज, ड्रैनेज एवं बरसाती जल प्रबन्धन आदि कार्य प्रगति पर हैं।	लगभग रू0 801.20 करोड़ की लागत से देहरादून तथा नैनीताल नगर में पेयजल, सीवरेज, ड्रैनेज एवं बरसाती जल प्रबन्धन आदि कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। DEA भारत सरकार ADB एवं शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा त्रिपक्षीय अनुबंध दिनांक 07.12.2021 को हस्ताक्षरित किया जा चुका है। देहरादून एवं नैनीताल नगर में 06 सब प्रोजेक्ट्स हेतु पेयजल, सीवरेज, ड्रैनेज एवं बरसाती जल प्रबन्धन आदि कार्य प्रगति पर हैं एवं नवीन पैकज हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।	देहरादून एवं नैनीताल में पेयजल अपव्यय तथा क्षरण में कमी किए जाने हेतु पेयजल सम्बन्धित कार्य किए जायेंगे। सीवरेज सम्बन्धित विकास कार्य किए जायेंगे। परियोजना के अन्तर्गत माह अक्टूबर–2023 तक ए0डी0बी को रू0 211.79 करोड़ के प्रतिपूर्ति दावे प्रेषित किये जा चुके है जिसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार से राज्य सरकार को कर दी गयी है। वर्तमान में परियोजना के अन्तगर्त वित्तीय वर्ष 2024–25 में ए0डी0बी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण किये जाने एवं परियोजना के अन्तर्गत देहरादून में डिफेंस कालोनी, नत्थनपुर, मोहकमपुर एवं नवादा में सीवरेज कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है। जिसके सापेक्ष अनुबंध उपरान्त 10 प्रतिशत मोबिलाइजेशन अग्रिम का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है इस प्रकार निर्माण कार्य हेतु पूंजीगत मद में रू 255.00 करोड़ एवं राजस्व मद में कार्यालय व्यय/अधिष्ठान एवं डी0एस0सी व्यय हेतु रू 25.00 करोड का व्यय किये जाने का अनुमान है।	उत्तराखण्ड के शहरी क्षेत्रों में स्थायी, सक्षम और उत्तरदायी सेवाओं के प्रतिपादन हेतु कार्य किया जाना, पर्यावरणीय स्थिरता को आसान बनाना इस परियोजना का समग्र उद्देश्य है। तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण विकास कार्यों में आने वाले अंतरालों की पहचान कर पहले से तैयार सभी बुनियादी अवस्थापनों को एकीकृत किया जाना। आधारभूत प्राथमिक शहरी सेवाओं (24x7) पेयजल, जल–मल प्रबंधन, बरसाती जल प्रबंधन, शहरी सड़क आदि) में शहरी जीवनशैली के स्तर अनुसार गुणवत्तापूर्ण सुधार। निकट भविष्य में नगरीय जनसंख्या के दबाव सहने योग्य तथा आकांक्षाओं पर खरा उतरने हेतु, सभी पर्याप्त सुविधाओं से सुसज्जित, सुनियोजित तंत्र का निर्माण करना।	2024–25

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले/बजट		01–04–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक स्थिति)	31–03–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2024–25	आउटकम हेतु संम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
15	**परियोजना (Phase-2) (ए0डी0बी)' मध्यम श्रेणी के नगर निकायों में षहरी अवस्थापन विकास (Uttarakhand Livablitiy & Improvement Project)** (बाह्य सहायतित योजना)	ADB के सहयोग से प्रथम चरण में चार जिलों (नैनीताल, देहरादून, पौडी, उधम सिंह नगर) के पांच नगर निकायों (हल्द्वानी, विकासनगर, चंपावत, कोटद्वार एवं किच्छा) में आधारभूत प्राथमिक शहरी सेवाओं (24x7) पेयजल, जल–मल प्रबंधन, बरसाती जल प्रबंधन, प्रशासनिक भवन, शहरी सड़क और यातायात सुधार आदि) में शहरी जीवनशैली के स्तर अनुसार गुणवत्तापूर्ण सुधार। निकट भविष्य में नगरीय जनसंख्या के दबाव सहने योग्य तथा जन आकांक्षाओं पर खरा उतरने हेतु, सभी पर्याप्त सुविधाओं सेसुसज्जित, सुनियोजित तंत्र का निर्माण करना।	1000.00	5000.00	परियोजना US$ 250 मीलियन (रू 2000 करोड) अनुमानित लागत की है जिसमें वित्त पोषित एव राज्य का 80:20 का अंश है। जिसके अन्तर्गत टेण्डर प्रक्रिया गतिमान है।	प्रथम चरण में चार जिलों (नैनीताल, देहरादून, पौडी, उधम सिंह नगर) के पांच नगर निकायों (हल्द्वानी, विकासनगर, चंपावत, कोटद्वार एवं किच्छा) हेतु टेण्डर प्रक्रिया गतिमान है।	प्रथम चरण में चार जिलों (नैनीताल, देहरादून, पौडी, उधम सिंह नगर) के पांच नगर निकायों (हल्द्वानी, विकासनगर, चंपावत, कोटद्वार एवं किच्छा) में 24X7 पेयजल, अपशिष्ट जल प्रबन्धन, बरसाती जल प्रबन्धन,प्रशासनिक भवन,शहरी सड़कें, यातायात और पार्किंग, वैंडिंग जोन, सूचना संपर्क तकनीकी और ओपन स्पेस जैसे कार्य किए जायेंगे। वित्तीय वर्ष 2024–25 में पैकजों के अनुबन्ध उपरान्त मोबिलाईजेशन एडवान्स एव पैकजो के भुगतान हेतु पूंजीगत मद में रू0 109.00 करोड़ एवं राजस्व मद में डी0एस0सी0/सर्वे इत्यादि व्यय हेतु रू0 10.00 करोड का व्यय किये जाने का अनुमान है।	परियोजना के अन्तर्गत नगरों में स्वचालित स्काडा तकनीक के द्वारा चौबीस घंटे पानी की सुविधा प्राप्त होगी, घरों में पेयजल मीटर लगाये जायेंगे ताकि पानी के अपव्यय को कम किया जा सके। सुरक्षित, स्वस्छ और स्वस्थ पर्यावरणीय परिस्थितियों को बनाये रखने हेतु अपशिष्ट जल प्रबन्धन किया जायेगा। बरसाती पानी के प्रबन्धन हेतु विकास कार्य किये जायेंगे। वहीं सड़कों व पार्किंग का निर्माण कर यातायात प्रबन्धन का कार्य भी किया जायेगा। छोटे फुटकर व्यापारियों हेतु वैन्डिंग जोन का निर्माण किया जायेगा। नियमित स्थानीय निकाय सुदृढ़ीकरण तथा सशक्तिकरण हेतु सूचना संचार तकनीकी का उपयोग किया जायेगा। इन सभी अवस्थापना विकास कार्यों के फलस्वरूप नगरीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा तथा नागरिक विकास स्तर भी सुदृढ़ होगा।	अनुबन्ध के पश्चात् समय सीमा निर्धारित किया जायेगा।है।

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले/बजट		01–04–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक स्थिति)	31–03–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2024–25	आउटकम हेतु संम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
17	परियोजना–हल्द्वानी एवं अन्य नगर एकीकृत शहरी अवस्थापना विकास **(Haldwani & Other Town –Additional Financing** वित्तपोषण एजेंसी (**Funding Agency)**– एशियन डेवेलपमेंट बैंक (**ADB)** से प्रस्तावित उत्तराखण्ड राज्य के हल्द्वानी शहर में आधारभूत प्राथमिक शहरी सेवाओं (24X7 पेयजल, जल–मल प्रबंधन, बरसाती जल प्रबंधन, शहरी सड़क और यातायात सुधार आदि कार्य किए जायेंगे।	उत्तराखण्ड राज्य के तीन जिलों (नैनीताल, देहरादून एवंचंपावत) के तीन नगर निकायों (हल्द्वानी, देहरादून एवं टनकपुरे)शहर में आधारभूत प्राथमिक शहरी सेवाओं (24X7 पेयजल, जल–मल प्रबंधन, बरसाती जल प्रबंधन, शहरी सड़क और यातायात सुधार आदि कार्य किए जायेंगे।	900.00	10000.00	परियोजना US$250 मीलियन (रू 2000 करोड) अनुमानित लागत की है जिसमें वित्त पोषित संस्था एव राज्य का 80:20 का अंश प्रतिशत है। जिसके अन्तर्गत टेण्डर प्रक्रिया गतिमान है।	उत्तराखण्ड राज्य के तीन जिलों (नैनीताल, देहरादून एवं चंपावत) के तीन नगर निकायों (हल्द्वानी, देहरादून एवं टनकपुरे) शहर हेतु टेण्डर प्रक्रिया गतिमान है। परियोजना के अन्तर्गत रू 2000 करोड़ के कार्यो को प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित है	वर्ष 24–25 में अनुबन्ध उपरान्त हल्द्वानी, देहरादून एवं टनकपुर शहर में 24X7 पेयजल, अपशिष्ट जल प्रबन्धन, बरसाती जल प्रबन्धन, शहरी सड़कें, यातायात और पार्किंग, वैंडिंग जोन कार्य किये जाने हेतु परियोजना में अनुबन्ध उपरान्त मोबिलाईजेशन एडवान्स एवं रनिंग देयकों के भुगतान हेतु पूंजीगत मद में रू0 179.00 करोड़ एवं राजस्व मद हेतु डी0एस0सी/सर्वे आदि कार्य हेतु रू 9.00 करोड़ के व्यय किये जाने का अनुमान है।	परियोजना के अन्तर्गत नगरों में स्वचालित स्काडा तकनीक के द्वारा चौबीस घंटे पानी की सुविधा प्राप्त होगी, घरों में पेयजल मीटर लगाये जायेंगे ताकि पानी के अपव्यय को कम किया जा सके। सुरक्षित, स्वस्छ और स्वस्थ पर्यावरणीय परिस्थितियों को बनाये रखने हेतु अपशिष्ट जल प्रबन्धन किया जायेगा। बरसाती पानी के प्रबन्धन हेतु विकास कार्य किये जायेंगे। वहीं सड़कों व पार्किंग का निर्माण कर यातायात प्रबन्धन का कार्य भी किया जायेगा। छोटे फुटकर व्यापारियों हेतु वैन्डिंग जोन का निर्माण किया जायेगा। नियमित स्थानीय निकाय सुदृढ़ीकरण तथा सशक्तिकरण हेतु सूचना संचार तकनीकी का उपयोग किया जायेगा। इन सभी अवस्थापना विकास कार्यों के फलस्वरूप नगरीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा तथा नागरिक विकास स्तर भी सुदृढ़ होगा।	अनुबन्ध के पश्चात् समय सीमा निर्धारित किया जायेगा।है।

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले/बजट		01–04–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक स्थिति)	31–03–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2024–25	आउटकम हेतु संम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
18	ऋषिकेश नगर एकीकृत षहरी अवस्थापना विकास परियोजना **(KFW)**	उत्तराखण्ड राज्य के ऋषिकेश शहर में आधारभूत प्राथमिक शहरी सेवाओं (24X7 पेयजल, जल–मल प्रबंधन, बरसाती जल प्रबंधन, शहरी सड़क और यातायात सुधार आदि कार्य किए जायेंगे।	1600.00	1100.00	परियोजना US$200मीलियन (रू 1600 करोड) अनुमानित लागत की है जिसमें वित्त पोषित संस्था एव राज्य का 80:20 का अंश प्रतिशत है। जिसके अन्तर्गत टेण्डर प्रक्रिया गतिमान है।	उत्तराखण्ड राज्य के ऋषिकेश शहर हेतु कन्सल्टेंट के चयन की टेण्डर प्रक्रिया गतिमान है। कन्सल्टेंट चयन उपरान्त डी0पी0आर0/सर्वे पर कार्य किया जाना प्रस्तावित है।	वर्ष 24–25 में ऋषिकेश शहर में 24X7 पेयजल, अपशिष्ट जल प्रबन्धन, बरसाती जल प्रबन्धन, शहरी सड़कें, यातायात और पार्किंग, वैंडिंग जोन कार्य किये जाने जिस हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 में रू 1000.00 करोड की निविदा आमंत्रित की जानी प्रस्तावित है जिसमें प्रस्तावित पैकजो के अनुबन्ध उपरान्त पूंजीगत मद में रू 11.00 करोड का व्यय किया जाना सम्भावित है एवं कन्सलटैन्सी चयन उपरान्त अनुबन्ध के आधार पर मोबिलाईजेशन एडवान्स एवं अधिष्ठान हेतु राजस्व मद में रू 16.00 करोड़ का व्यय किये जाने का अनुमान है।	परियोजना के अन्तर्गत नगरों में स्वचालित स्काडा तकनीक के द्वारा चौबीस घंटे पानी की सुविधा प्राप्त होगी, घरों में पेयजल मीटर लगाये जायेंगे ताकि पानी के अपव्यय को कम किया जा सके। सुरक्षित, स्वस्छ और स्वस्थ पर्यावरणीय परिस्थितियों को बनाये रखने हेतु अपशिष्ट जल प्रबन्धन किया जायेगा। बरसाती पानी के प्रबन्धन हेतु विकास कार्य किये जायेंगे। वहीं सड़कों व पार्किंग का निर्माण कर यातायात प्रबन्धन का कार्य भी किया जायेगा। छोटे फुटकर व्यापारियों हेतु वैन्डिंग जोन का निर्माण किया जायेगा। नियमित स्थानीय निकाय सुदृढ़ीकरण तथा सशक्तिकरण हेतु सूचना संचार तकनीकी का उपयोग किया जायेगा। इन सभी अवस्थापना विकास कार्यों के फलस्वरूप नगरीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा तथा नागरिक विकास स्तर भी सुदृढ़ होगा।	2024–25

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले / बजट		01–04–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक स्थिति)	31–03–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2024–25	आउटकम हेतु संम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
17	सफाई कर्मचारियों का बीमा	नगर निकायों में सफाई कर्मचारी नगरों की सफाई व्यवस्था, नालीयो, सीवरेज आदि की सफाई व्यवस्था का कार्य करते है । कोबिड समय में भी सफाई कर्मचारियों द्वारा शहरो तथा कोबिड सेन्टरो की सफाई में विशेष योगदान दिया है । सफाई कर्मचारी कठिन परिस्थितियों में भी सफाई व्यवस्था का कार्य करते है, जिसके कारण इनके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा बीमा योजना के अर्न्तगत बीमित करने का प्रस्ताव है।	88.00	00.00	नवीन योजना	नवीन योजना	स्थानीय निकायों में 4216 नियमित सफाई कर्मचारियों के बीमा की कोई व्यवस्था नही है। मृत्यु पर उनके परिवार को बीमा कोई लाभ प्राप्त नही होता है। सफाई कर्मचारियों को सुरक्षा बीमा योजना के अर्न्तगत बीमित किये जायगें।	नगर निकायों के सफाई कर्मचारियों को बीमित करने पर बीमा कम्पनी को भुगतान की जायेगी कुल रू0 88.00 लाख का व्यय किया जाना प्रस्तावित है।	2024–25

आउटकम बजट 2024– 25

शहरी विकास विभाग

विभाग के अर्न्तगत प्रस्तावित ए0डी0जी0– एस0डी0जी0–1

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	**प्रस्तावित आउट ले** लाख रूपये में		01–04–2023 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31–03–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2024–25	आउटकम हेतु संम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
19	राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (NULM)	शहरी क्षेत्र में रह रहे गरीब परिवारों का सामाजिक व आर्थिक क्षमता विकास करते हुये प्रशिक्षण तथा वित्तीय सहायता के माध्यम से रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना एवं उनकी आजीविका को मजबूत करना है। जिससे वह सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें।	500.00	0.02	1.सामाजिक संगठन एवं संस्था विकास के अन्तर्गत 3261 महिला स्वयं सहायता समूहों व 102 क्षेत्र स्तरीय संघ का गठन 21000 महिलाओ का आजीविका संवर्द्धन। 2..स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्तर्गत 7944 लाभार्थियों ऋण वितृत किया गया। 3.शहरी पथ विक्रेताओं की सहायता के अन्तर्गत 5238 स्ट्रीट वेण्डर को पहचान पत्र वितरित। 4. शहरी निराश्रितों हेतु 14 रैन बसेरा का निर्माण स्वीकृत, जिसके सापेक्ष 11 रैन बसेरो का संचालन प्रारम्भ। 5.कौशल विकास के अंतर्गत 18512 लाभार्थियों को रोजगारपरक पाठ्यक्रम मे प्रशिक्षण 7559 लाभार्थियों को रोजगार व 607 लाभार्थियों का स्वरोजगार से जुड़ाव।	➢ सामाजिक संगठन एवं संस्था विकास के अन्तर्गत 3983 महिला स्वयं सहायता समूहों 131 क्षेत्र स्तरीय संघ का गठन 36000 महिलाओ का आजीविका संवर्द्धन। ➢ स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 8567 को व्यक्तिगत ऋण विस्तृत किया गया। ➢ शहरी निराश्रितों हेतु 14 रैन बसेरा का निर्माण स्वीकृत, जिसके सापेक्ष 12 रैन बसेरो का संचालन प्रारम्भ व 02 रैन बसेरे निर्माणाधीन।	➢ सामाजिक संगठन एवं संस्था विकास के अन्तर्गत 4280 महिला स्वयं सहायता समूहों व 200 क्षेत्र स्तरीय संघ का गठन 40000 महिलाओ का आजीविका संवर्द्धन। ➢ स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 9500 व्यक्तिगत ऋण वितरित किये जाने का लक्ष्य है। स्वीकृत 14 रैन बसेरा का निर्माण पूर्ण किया जायेगा।	➢ राज्य में शहरी क्षेत्रो मे गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूह क्षेत्र स्तरीय नगरस्तरीय संघ के माध्यम से उनकी आजीविका में सुधार होगी। ➢ .कौशल विकास प्रशिक्षणों के माध्यम से बेरोजगारों हेतु मांगानुरूप प्रशिक्षण आयोजित कर 70 प्रतिशत लाभार्थियो कोरोजगार/स्वरोजगार से जुड़ाव तथा उनकी आजीविका में सुधार होगी। संस्थागत ऋण उपलब्ध होगा एवं सामाजिक सुरक्षा तथा स्वरोजगार के माध्यम से शहरी गरीबों का आजीविका के स्तरको बढ़ावा मिलेगा। ➢ शहरी पथ विक्रेताओं आजीविका हेतु उन्हें उपयुक्त स्थान,सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध होगी।	2024–25

<u>आउटकम बजट 2024– 25</u>

शहरी विकास विभाग

विभाग के अर्न्तगत प्रस्तावित एस0जी0जी0 –एस0डी0जी0–11 व 12

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	**प्रस्तावित आउट ले** लाख रूपये में		01–04–2023 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31–03–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2024–25	आउटकम हेतु संम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
20	अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन	भारत सरकार द्वारा नगर निगम देहरादून, हरिद्वार, रूड़की, काशीपुर रूद्रपुर हल्द्वानी–काठगोदाम तथा नगर पालिका परि0 नैनीताल में अमृत योजना प्रत्येक परिवार को निश्चित जलापूर्ति व सीवेज कनैक्शन उपलब्ध कराना। 2. हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान (अर्थात पार्क) विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्धि करना ।	6.50	-	जलापूर्ति (लक्ष्य–47 योजना) के सापेक्ष 10 योजनाएं पूर्ण, 37 योजनाओं कार्य प्रगति पर। सीवरेज (लक्ष्य–44 योजना) के सापेक्ष 25 योजनाएं पूर्ण, 19 योजनाओं कार्य प्रगति पर। ड्रेनेज (लक्ष्य–16) 6 पूर्ण, 10 योजनाओं का कार्य प्रगति पर। ग्रीनस्पेस/पार्क (लक्ष्य–44) के सापेक्ष 24 योजनाए पूर्ण, 20 योजनाओं का कार्य प्रगतिपर।	➢ जलापूर्ति (लक्ष्य–47 योजना) के सापेक्ष 44 योजनाएं पूर्ण। ➢ सीवरेज (लक्ष्य–44 योजना) के सापेक्ष 43 योजनाएं पूर्ण। ➢ ड्रेनेज सेक्टर (लक्ष्य–16) 15 योजनाएं पूर्ण। ➢ ग्रीन स्पेस/पार्क सेक्टर (लक्ष्य–44) के सापेक्ष 42 योजनाएं पूर्ण। ➢ नैनीताल, हल्द्वानी, रूद्रपुर, काशीपुर, देहरादून, हरिद्वार, रूड़की के लिए मास्टर प्लान तैयार किये जाने हेतु जी0आई0एस0 मैपिंग का काम प्रगति पर है।	➢ जलापूर्ति सेक्टर 47 योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जायेगा। ➢ सीवरेज सेक्टर 44 योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जायेगा। ➢ ड्रेनेज सेक्टर 12 योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जायेगा। ➢ ग्रीन स्पेस/पार्क सेक्टर 44 योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जायेगा। ➢ नैनीताल, हल्द्वानी, रूद्रपुर, काशीपुर, देहरादून, हरिद्वार, रूड़की के लिए मास्टर प्लान तैयार किये जाने हेतु जी0आई0एस0 मैपिंग कार्य पूर्ण करना	➢ लोगों को यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार को निश्चित जलापूर्ति व सीवरेज कनैक्शन सहित नल सुलभ है। ➢ बाढ़ को कम करने और समाप्त करने के उद्देश्य से नालों व वर्षा जन नालों का निर्माण और सुधार। ➢ हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान (अर्थात पार्क) विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्धि करना। ➢ जी0आई0एस0 मैपिंग के फलस्वरूप अमृत शहरों के अन्तर्गत विकास कार्यों के लिए परियोजना तैयार करने में सुविधा होगी।	2024–25

आउटकम बजट 2024–25
शहरी विकास विभाग
विभाग के अर्न्तगत प्रस्तावित एस0डी0जी0–एस0डी0जी0 01,06, व 11

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	**प्रस्तावित आउट ले** लाख रूपये में		01–04–2023 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31–03–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2024–25	आउटकम हेतु संम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
21	प्रधानमन्त्री आवास योजना	प्रधानमन्त्री आवास परियोजनान्तर्गत सभी नगर निकायों में निवासरत लोगों को बेहतर सुख–सुविधाओं के साथ आवास उपलब्ध कराना है। इस योजनान्तर्गत जिनके व्यक्तियों के पास अपना आवास नही है तथा जीर्ण–शीर्ण दशाओं में रहते है की दशा में सुधार करने के लिये एक दृष्टिकोण अपनाते हुए लाभान्वित करते हुए बुनियादी अवस्थापना सुविधाएं जैसेः–बेहतर समेकित विकास, जलापूर्ति – सफाई सुविधा, आदि उपलब्ध करने प्रयास करना है।	22100.00	-	योजनान्तर्गत 7640 आवास पूर्ण किये गये है तथा 8105 मकान का काम प्रगति पर है ।	➢ योजनान्तर्गत लाभार्थी आधारित घटक अंतर्गत 316 परियोजनाओं में 25760 आवास स्वीकृत 16378 आवासों पर कार्य प्रगति पर जिनमें से 11860 आवास पूर्ण होने सम्भावित है। ➢ भागीदारी में किफायती आवास घटक अंतर्गत 20 परियोजनाओं में 15960 आवास स्वीकृत 1344 पर कार्य पूर्ण तथा 14616 आवासों पर कार्य प्रगति पर।	➢ योजनान्तर्गत लाभार्थी आधारित घटक अंतर्गत 4518 आवास को पूर्ण करा लिया जायेगा। ➢ भागीदारी में किफायती आवास घटक अंतर्गत 14616 आवासों को पूर्ण कराने लक्षित है।	➢ इस परियोजना के अन्तर्गत आवासों का निर्माण करते हुए शहरी क्षेत्र में लोगों को अपना आवास तथा बुनियादी अवस्थापना सुविधाएं जैसेः– बेहतर समेकित विकास, जलापूर्ति–सफाई सुविधा, आदि उपलब्ध होगी।	2024–2025

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	आउट ले/बजट		01–04–2023 की वास्तविक स्थिति (भौतिक स्थिति)	31–03–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम वर्ष 2024–25	आउटकम हेतु संम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
22	स्वच्छ भारत मिशन	स्वच्छ भारत मिशन के मुख्य उद्देश्य ''खुले में शौच'' की प्रवृत्ति का उन्मूलन। मैला ढोने की प्रवृत्ति का उन्मूलन। आधुनिक और वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ठ प्रबन्धन। स्वच्छता से सम्बन्धित जन व्यवहार में परिवर्तन। स्वच्छता के प्रति तथा स्वच्छता के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जागरूकता लाना। नगर निकायों की क्षमता अभिवृद्धि करना है।	-	500.00	1–26843 व्यक्तिगत शौचालय पूर्ण निर्मित। 2–2231 सीट के सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय पूर्ण। 3–698 सीट के सार्वजनिक मूत्रालय पूर्ण निर्मित। 4- कुल 1152 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा एकत्र किया जा रहा है।	1–27640 व्यक्तिगत शौचालय पूर्ण निर्मित । 2–2798 सीट के सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय पूर्ण । 3–1000 सीट के सार्वजनिक मूत्रालय पूर्ण निर्मित । 4- कुल 1242 वार्डों में से घर–घर कूड़ा एकत्रण तथा 1200 वार्डो में Source Segregation ।	1– 41 निकायों में ठोस अपषिष्ट प्रबन्धन का कार्य पूर्ण कराया जाना ।	➢ .जिन घरों में शौचालय नहीं थे उन घरों में शौचालय का निर्माण। ➢ नगरों में खुले में शौच की प्रवृत्ति का उन्मूलन। ➢ नगरों में स्वच्छता और सफाई की सुनिश्चिता। ➢ ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक रूप से निस्तारण।	2024–25

आउटकम बजट 2024– 25

शहरी विकास विभाग

विभाग के अंतर्गत प्रस्तावित एस०डी०जी० : एस०डी०जी० – 01, 06, 11 व 12 वित्तीय लाख रूपये में

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	प्रस्तावित आउट ले		01–04–2023 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31–03–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2024–25	आउटकम हेतु संम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
23	स्मार्ट सिटी योजना	स्मार्ट सिटी के अर्न्तगत देहरादून शहर का चयन किया गया है, जिसके अर्न्तगत शहर का सुनियोजित विकास किया जायेगा।	-	4650.00	–परियोजना के अन्तर्गत इन्ट्रीग्रेटेड कमांड कन्ट्रोल का कार्य, परेड ग्राउंड कायाकल्प, पल्टन बाजार, वाटर ए0टी0एम0, क्रेच बिल्डिंग, स्मार्ट टायलेट, स्मार्ट स्कूल, मॉडर्न दून लाईब्रेरी, इलैक्ट्रिक बस, स्मार्ट वॉटर मैनेजमेंट निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। –परियोजना के अन्तर्गत स्मार्ट रोड, इंटीग्रेटेड ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण कार्य प्रारम्भ। –इंटीग्रेटेड ऑफिस काम्पलेक्स ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भ किया जाएगा।	➢ इंटीग्रेटेड ड्रेनेज सिस्टम का कार्य 30 मार्च 2024 तक पूर्ण हो जाएगा। ➢ इंटीग्रेटेड सीवेरज का कार्य 30 मार्च 2024 तक पूर्ण हो जाएगा। ➢ स्मार्ट रोड़ का कार्य 30 मार्च 2024 तक पूर्ण हो जाएगा।	➢ वर्तमान में शहर के विभिन्न स्थानों में वर्षा के दौरान जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जिसके लिए एक बेहतर ड्रेनेज सिस्टम प्रस्तावित किया गया है। ➢ ए0बी0डी0 एरिया में सीवर लाइन काफी पुरानी है और उसे बदले जाने का प्रस्ताव है। जिससे शहर में सीवरेज लाइन समस्या का निस्तारण किया जयेगा। ➢ स्मार्ट रोड के कार्य में सड़कों के दोनों ओर डक्ट बनाई जायेगी जिसमें बिजली, पानी की लाईन डाली जायेगी जिससे तारो का जाल हट जयेगा साथ ही सड़को पर बेतरतीब खड़ें बिजली के खम्बो के हटने से भी यातायात संचालन में सुविधा रहेगी। उक्त कार्य मार्च 2024 तक समाप्त कर दिया जायेगा। ➢ ग्रीन बिल्डिंग में 73 सरकारी विभागों को स्थान्तरित किया जा रहा है जिससे आम जनता को एक ही स्थान पर सभी कार्यालय होने से लाभ प्राप्त होगा तथा कार्य सितम्बर, 2026 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।	➢ देहरादून नगर का सुनियोजित विकास होगा जिससे बेहतर पेयजल व्यवस्था सीवरेज, यातायात की सुविधा निवासियों को उपलब्ध होगी। ➢ इंटीग्रेटेड ऑफिस काम्पलेक्स ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण से आम जनता को एक ही स्थान पर समस्त कार्यालय की सुविधा उपलब्ध होगी।	2024–25

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	प्रस्तावित आउट ले		01–04–2023 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31–03–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2024–25	आउटकम हेतु संम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
24	स्मार्ट सिटी CITIIS	सिटी इन्वेस्टमेन्ट इनोवेट इटीग्रेड एण्ड सस्टेन (CITIIS) के अर्न्तगत फुटपाथो का निर्माण,रैलिग, ओबरब्रिज आदि का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है ।	-	1000.00	–CITIES परियोजना कार्य का 2 फेज़ में विभाजन किया गया है। फेज–1 में कुल विद्याालयों की संख्या 46 है एवं फेज–2 के अंतर्गत 74 विद्यालयों को चयनित कया गया है। – फेज–1 का कार्य प्रगति पर है। – फेज–2 का निर्माण कार्य प्रारम्भ।	➢ 26.02.2024 तक कार्य पूर्ण हो जाएगा।	देहरादून शहर में बच्चों के स्कूल आने जाने के लिए पर्याप्त फुटपाथो का निर्माण, फुटपाथो की रैलिग, ओवरब्रिज, आदि का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है।	बच्चों के स्कूल आने जाने के लिए पर्याप्त फुटपाथों का निर्माण, फुटपाथों की रेलिंग, ओवरब्रिज आदि का निर्माण से यातायात सुगम होगा।	2024–25

आउटकम बजट 2024 – 25

शहरी विकास विभाग

विभाग के अंतर्गत प्रस्तावित एस०डी०जी० : एस०डी०जी० –1,11 व 12

क्र0 सं0	योजना का नाम	योजना के उद्देश्य	**प्रस्तावित आउट ले** लाख रूपये में		01–04–2023 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31–03–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2024–25	आउटकम हेतु संम्भावित समयावधि
			राजस्व	पूंजीगत					
25	अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन– 02	अमृत–02 के अर्न्तगत अमृत शहरो में अवशेष सीवरेज तथा समस्त नगर निकायों में पेयजल एवं जलापूर्ति के कार्य कराये जायेगे। प्रत्येक परिवार को पेयजल नल उपलब्ध करायेगे।	1630.00	8320.00	योजना वित्तीय वर्ष 2022–23 से प्रारम्भ की गयी।	योजना वित्तीय वर्ष 2022–23 से प्रारम्भ की गयी जिसके अन्तर्गत 08 निकायों में पेयजल का कार्य प्रगति पर है।	योजना वित्तीय वर्ष 2022–23 से प्रारम्भ की गयी , जिसे समस्त नगर निकायों में पेयजल का सर्वेक्षण कराकर परियोजनायें अनुमोदित कराकर धनावटन हेतु भारत सरकार को प्रेषित की जायेगी। अमृत शहरो सीवरेज का अवशेष कार्य निर्मित करना नगर निकायों में पेयजल योजनाये निर्मित कराना।	लोगों को यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार को निश्चित जलापूर्ति नल सुलभ है।	2024–25
27	स्वच्छ भारत मिशन –02	स्वच्छ भारत मिशन के मुख्य उद्देश्य ''खुले में शौच'' की प्रवृत्ति का उन्मूलन। मैला ढोने की प्रवृत्ति का उन्मूलन। आधुनिक और वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन स्वच्छता से सम्बन्धित जन व्यवहार में परिवर्तन। स्वच्छता के प्रति तथा स्वच्छता के सार्वजनिक स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जागरूकता लाना। नगर निकायों की क्षमता अभिवृद्धि करना है।	1609.00	4977.00	1–लीगेसी वेस्ट के उपचार हेतुं 08 डी0पी0आर भारत सरकार से स्वीकृति। 2–व्यक्तिगत घरेलू ष्षौचालय, सार्वजनिक ष्षौचालय, आई0ई0सी0 व क्षमता अभिवृद्धि कार्य–योजना भारत सरकार से स्वीकृति, धनराषि प्राप्त किया जाना।	लीगेसी वेस्ट के उपचार हेतु 07 अन्य नगरों की डी0पी0आर के सापेक्ष भारत सरकार से धनराषि प्राप्त किया जाना। 2–व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक मूत्राालय, आई0ई0सी0 व क्षमता अभिवृद्धि कार्य–योजना के सापेक्ष भारत सरकार से स्वीकृति, धनराषि प्राप्त किया जाना।	1–3000 व्य0 शौचालय का निर्माण । 2–110 सीट के सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय का निर्माण। 3–70 सीट के सार्वजनिक मूत्रालय का निर्माण। 4-14 निकायों में लिगेसी वेस्ट निस्तारण का कार्य प्रारम्भ।	➢ .जिन घरों में शौचालय नहीं थे उन घरों में शौचालय का निर्माण। ➢ नगरों में खुले में शौच की प्रवृत्ति का उन्मूलन। ➢ नगरों में स्वच्छता और सफाई की सुनिश्चिता। ➢ लीगेसी वॉटर निस्तारण कर भूमि का पुनः उपयोग	2024–25

सतत् विकास लक्ष्यों हेतु प्रारूप 2024–25

शहरी विकास विभाग

क्र0 सं0	एस०डी० जी० Goals / Indicators	01–04–2023 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31–03–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2024–25
1	1.No Poverty No of homeless household Functional SHGs to total SHGs formed Share of credit linked SHGs under NULM to total SHGs	1.सामाजिक संगठन एवं संस्था विकास के अन्तर्गत 3261 महिला स्वयं सहायता समूहों व 102 क्षेत्र स्तरीय संघ का गठन 21000 महिलाओ का आजीविका संवर्द्धन। 2.स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत अन्तर्गत 7944 लाभार्थियों ऋण वितृत किया गया। 3.शहरी पथ विकेताओं की सहायता के अन्तर्गत 5238 स्ट्रीट वेण्डर को पहचान पत्र वितरित। 4. शहरी निराश्रितों हेतु 14 रैन बसेरा का निर्माण स्वीकृत, जिसके सापेक्ष 11 रैन बसेरो का संचालन प्रारम्भ। 5.कौशल विकास के अंतर्गत 18512 लाभार्थियों को रोजगारपरक पाठ्यक्रम मे प्रशिक्षण 7559 लाभार्थियों को रोजगार व 607 लाभार्थियों का स्वरोजगार से जुड़ाव।	➢ सामाजिक संगठन एवं संस्था विकास के अन्तर्गत 3983 महिला स्वयं सहायता समूहों 131 क्षेत्र स्तरीय संघ का गठन 36000 महिलाओ का आजीविका संवर्द्धन। ➢ स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 8567 को व्यक्तिगत ऋण वितृत किया गया। ➢ शहरी निराश्रितों हेतु 14 रैन बसेरा का निर्माण स्वीकृत, जिसके सापेक्ष 12 रैन बसेरो का संचालन प्रारम्भ व 02 रैन बसेरे निर्माणाधीन।	➢ सामाजिक संगठन एवं संस्था विकास के अन्तर्गत 4280 महिला स्वयं सहायता समूहों व 200 क्षेत्र स्तरीय संघ का गठन 40000 महिलाओ का आजीविका संवर्द्धन। ➢ स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल 9500 व्यक्तिगत ऋण वितरित किये जाने का लक्ष्य है। ➢ स्वीकृत, 12 रैन बसेरो का निर्माण पूर्ण किया जायेंगा।	➢ राज्य में शहरी क्षेत्रो मे गरीब महिलाओं को स्वयं सहायता समूह क्षेत्र स्तरीय नगरस्तरीय संघ के माध्यम से उनकी आजीविका में सुधार होगी। ➢ कौशल विकास प्रशिक्षणों के माध्यम से बेरोजगारों हेतु मांगानुरूप प्रशिक्षण आयोजित कर 70 प्रतिशत लाभार्थियो को रोजगार/ स्वरोजगार से जुड़ाव तथा उनकी आजीविका में सुधार होगी। संस्थागत ऋण उपलब्ध होगा एवं सामाजिक सुरक्षा तथा स्वरोजगार के माध्यम से शहरी गरीबों का आजीविका के स्तरको बढ़ावा मिलेगा। ➢ शहरी पथ विक्रेताओं आजीविका हेतु उन्हें उपयुक्त स्थान, सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध होगी।
	% age HH covered in Urban areas वर्तमान में 05 प्रतिशत जो कि 1.04 लाख है को योजना में लाभांवित किया जाना है।	प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत 7640 आवास पूर्ण किये गये है तथा 8105 मकान का काम प्रगति पर है ।	➢ योजनान्तर्गत लाभार्थी आधारित घटक अंतर्गत 316 परियोजनाओं में 25760 आवास स्वीकृत 16378 आवासों पर कार्य प्रगति पर जिनमें से 11860 आवास पूर्ण होने सम्भावित है। भागीदारी में किफायती आवास घटक अंतर्गत 20 परियोजनाओं में 15960 आवास स्वीकृत 1344 पर कार्य पूर्ण तथा 14616	➢ योजनान्तर्गत लाभार्थी आधारित घटक अंतर्गत 4518 आवास को पूर्ण करा लिया जायेगा। ➢ भागीदारी में किफायती आवास घटक अंतर्गत 14616 आवासों को पूर्ण कराने लक्षित है।	➢ इस परियोजना के अन्तर्गत आवासों का निर्माण करते हुए शहरी क्षेत्र में लोगों को अपना आवास तथा बुनियादी अवस्थापना सुविधाएं जैसेः– बेहतर समेकित विकास, जलापूर्ति–सफाई सुविधा, आदि उपलब्ध होगी।

क्र0 सं0	एस०डी० जी० Goals / Indicators	01–04–2023 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31–03–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2024–25
			आवासों पर कार्य प्रगति पर।		
	% age of households by IHHL (urban)स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत लाभांवित किया जाना है। % age of slum areas covered - 30 प्रतिशत % age of households by IHHL (urban) शेष 04 प्रतिशत जनसंख्या का आच्दित किया जाना है। % age of door to door waste collection- 93 प्रतिशत डोर – 2 – डोर कुडा संग्रहण किया जा रहा है।	1–26843 व्यक्तिगत शौचालय पूर्ण निर्मित। 2–2231 सीट के सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय पूर्ण। 3–698 सीट के सार्वजनिक मूत्रालय पूर्ण निर्मित। 4- कुल 1152 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा एकत्र किया जा रहा है।	1–27640 व्यक्तिगत शौचालय पूर्ण निर्मित । 2–2798 सीट के सामुदायिक/सार्वजनिक शौचालय पूर्ण । 3–1000 सीट के सार्वजनिक मूत्रालय पूर्ण निर्मित । 4- कुल 1242 वार्डों में से घर–घर कूड़ा एकत्रण तथा 1200 वार्डो में Source Segregation ।	1– 41 निकायों में ठोस अपषिष्ट प्रबन्धन का कार्य पूर्ण कराया जाना।	➢ .जिन घरों में शौचालय नहीं थे उन घरों में शौचालय का निर्माण। ➢ नगरों में खुले में शौच की प्रवृत्ति का उन्मूलन। ➢ नगरों में स्वच्छता और सफाई की सुनिश्चिता। ➢ ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक रूप से निस्तारण।
2	6 Clean water and sanitation	08 निकायों में अवस्थापना विकास जैसे नाला, नालियों, खडंजा, सुरक्षा दीवार, पार्किंग आदि का निर्माण।	45 निकायों में अवस्थापना विकास जैसे नाला, नालियों, खडंजा, सुरक्षा दीवार, पार्किंग आदि का निर्माण।	नगरीय निकायो में अवस्थापना विकास जैसे नाला, नालियों, खडंजा, सुरक्षा दीवार, पार्किंग आदि का निर्माण।	नगरीय अवस्थापना में विकास किया जायेगा। जिससे नगरीय क्षेत्रों में खराब नाले सड़को ड्रेनेज तथा निकाय क्षेत्र के अन्तर्गत पार्किंग व्यवस्था सुदृढ़ हो जायेगी।
		नगर पंचायत, पोखरी को रू0 6.744 लाख की धनराशि स्वीकृत हुआ है।	नगर निकाय अल्मोड़ा, नौगांव, काशीपुर, भवाली, लम्बगांव, कपकोट तथा गरूड़ में निर्मित कराये जायेगे।	20 नगर निकायों में पर्यटकों तथा आम जनता की सुविधा हेतु स्वच्छ शौचालय, बाथरूम की व्यवस्था होगी । साथ ही जिला मुख्यालय के शहरों में नये हाईटेक शौचालय निर्माण कराये जायेगे।	नगर निकायों में पर्यटकों तथा आम जनता की सुविधा हेतु स्वच्छ शौचालय, बाथरूम की व्यवस्था की गयी है

क्र0 सं0	एस०डी० जी० Goals / Indicators	01–04–2023 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31–03–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2024–25
2	6.Clean water and sanitation	भारत सरकार के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य में ADB के सहयोग से 02 शहरों (देहरादून एवं नैनीताल) में नगरीय अवस्थापना जैसे सीवरेज, वॉटर सप्लाई का सुदृढ़ीकरण व विकास कार्य प्रगति पर है। ● वाटर सप्लाई –74 कि.मी. ● सीवर –185 कि.मी. ● एस0टी0पी0–कार्य प्रगति पर है। ● सीवर कनैक्शन–16385 नग। DEA भारत सरकार, ADB एवं शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा त्रिपक्षीय अनुबंध दिनांक 07.12.2021 को हस्ताक्षरित किया जा चुका है। देहरादून एवं नैनीताल नगर में 06 सब प्रोजेक्ट्स हेतु पेयजल, सीवरेज, ड्रैनेज एवं बरसाती जल प्रबन्धन आदि कार्य प्रगति पर हैं।	लगभग रू0 801.20 करोड़ की लागत से देहरादून तथा नैनीताल नगर में पेयजल, सीवरेज, ड्रैनेज एवं बरसाती जल प्रबन्धन आदि कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। DEA भारत सरकार ADB एवं शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा त्रिपक्षीय अनुबंध दिनांक 07.12.2021 को हस्ताक्षरित किया जा चुका है। देहरादून एवं नैनीताल नगर में 06 सब प्रोजेक्ट्स हेतु पेयजल, सीवरेज, ड्रैनेज एवं बरसाती जल प्रबन्धन आदि कार्य प्रगति पर हैं एवं नवीन पैकज हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।	देहरादून एवं नैनीताल में पेयजल अपव्यय तथा क्षरण में कमी किए जाने हेतु पेयजल सम्बन्धित कार्य किए जायेंगे। सीवरेज सम्बन्धित विकास कार्य किए जायेंगे। परियोजना के अन्तर्गत माह अक्टूबर–2023 तक ए0डी0बी को रू0 211.79 करोड़ के प्रतिपूर्ति दावे प्रेषित किये जा चुके है जिसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार से राज्य सरकार को कर दी गयी है। वर्तमान में परियोजना के अन्तगर्त वित्तीय वर्ष 2024–25 में ए0डी0बी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण किये जाने एवं परियोजना के अन्तर्गत देहरादून में डिफेंस कालोनी, नत्थनपुर, मोहकमपुर एवं नवादा में सीवरेज कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है। जिसके सापेक्ष अनुबंध उपरान्त 10 प्रतिशत मोबिलाइजेशन अग्रिम का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है इस प्रकार निर्माण कार्य हेतु पूंजीगत मद में रू 255.00 करोड़ एवं राजस्व मद में कार्यालय व्यय/अधिष्ठान एवं डी0एस0सी व्यय हेतु रू 25.00 करोड का व्यय किये जाने का अनुमान है।	उत्तराखण्ड के शहरी क्षेत्रों में स्थायी, सक्षम और उत्तरदायी सेवाओं के प्रतिपादन हेतु कार्य किया जाना, पर्यावरणीय स्थिरता को आसान बनाना इस परियोजना का समग्र उद्देश्य है। तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण विकास कार्यों में आने वाले अंतरालों की पहचान कर पहले से तैयार सभी बुनियादी अवस्थापनों को एकीकृत किया जाना। आधारभूत प्राथमिक शहरी सेवाओं (24x7) पेयजल, जल–मल प्रबंधन, बरसाती जल प्रबंधन, शहरी सड़क आदि) में शहरी जीवनशैली के स्तर अनुसार गुणवत्तापूर्ण सुधार। निकट भविष्य में नगरीय जनसंख्या के दबाव सहने योग्य तथा आकांक्षाओं पर खरा उतरने हेतु, सभी पर्याप्त सुविधाओं से सुसज्जित, सुनियोजित तंत्र का निर्माण करना।

क्र0 सं0	एस०डी० जी० Goals / Indicators	01–04–2023 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31–03–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2024–25
		बाह्य सहायतित योजना–2 परियोजना US$ 250 मीलियन (रू 2000 करोड) अनुमानित लागत की है जिसमें वित्त पोषित एव राज्य का 80:20 का अंश है। जिसके अन्तर्गत टेण्डर प्रक्रिया गतिमान है।	प्रथम चरण में चार जिलों (नैनीताल, देहरादून, पौडी, उधम सिंह नगर) के पांच नगर निकायों (हल्द्वानी, विकासनगर, चंपावत, कोटद्वार एवं किच्छा) हेतु टेण्डर प्रक्रिया गतिमान है।	प्रथम चरण में चार जिलों (नैनीताल, देहरादून, पौडी, उधम सिंह नगर) के पांच नगर निकायों (हल्द्वानी, विकासनगर, चंपावत, कोटद्वार एवं किच्छा) में 24X7 पेयजल, अपशिष्ट जल प्रबन्धन, बरसाती जल प्रबन्धन, प्रशासनिक भवन, शहरी सड़कें, यातायात और पार्किंग, वैंडिंग जोन, सूचना संपर्क तकनीकी और ओपन स्पेस जैसे कार्य किए जायेंगे। वित्तीय वर्ष 2024–25 में पैकजों के अनुबन्ध उपरान्त मोबिलाईजेशन एडवान्स एव पैकजो के भुगतान हेतु पूंजीगत मद में रू0 109.00 करोड़ एवं राजस्व मद में डी0एस0सी0/सर्वे इत्यादि व्यय हेतु रू0 10.00 करोड का व्यय किये जाने का अनुमान है।	परियोजना के अन्तर्गत नगरों में स्वचालित स्काडा तकनीक के द्वारा चौबीस घंटे पानी की सुविधा प्राप्त होगी, घरों में पेयजल मीटर लगाये जायेंगे ताकि पानी के अपव्यय को कम किया जा सके। सुरक्षित, स्वस्छ और स्वस्थ पर्यावरणीय परिस्थितियों को बनाये रखने हेतु अपशिष्ट जल प्रबन्धन किया जायेगा। बरसाती पानी के प्रबन्धन हेतु विकास कार्य किये जायेंगे। वहीं सड़कों व पार्किंग का निर्माण कर यातायात प्रबन्धन का कार्य भी किया जायेगा। छोटे फुटकर व्यापारियों हेतु वैन्डिंग जोन का निर्माण किया जायेगा। नियमित स्थानीय निकाय सुदृढ़ीकरण तथा सशक्तिकरण हेतु सूचना संचार तकनीकी का उपयोग किया जायेगा। इन सभी अवस्थापना विकास कार्यों के फलस्वरूप नगरीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा तथा नागरिक विकास स्तर भी सुदृढ़ होगा।
		जलापूर्ति (लक्ष्य–47 योजना) के सापेक्ष 10 योजनाएं पूर्ण, 37 योजनाओं कार्य प्रगति पर। सीवरेज (लक्ष्य–44 योजना) के सापेक्ष 25 योजनाएं पूर्ण, 19 योजनाओं कार्य प्रगति पर। ड्रेनेज (लक्ष्य–16) 6 पूर्ण, 10 योजनाओं का कार्य प्रगति पर। ग्रीनस्पेस/पार्क (लक्ष्य–44) के सापेक्ष 24 योजनाए पूर्ण, 20 योजनाओं का कार्य प्रगतिपर।	➢ जलापूर्ति (लक्ष्य–47 योजना) के सापेक्ष 44 योजनाएं पूर्ण। ➢ सीवरेज (लक्ष्य–44 योजना) के सापेक्ष 43 योजनाएं पूर्ण। ➢ ड्रेनेज सेक्टर (लक्ष्य–16) 15 योजनाएं पूर्ण। ➢ ग्रीन स्पेस/पार्क सेक्टर (लक्ष्य–44) के सापेक्ष 42 योजनाएं पूर्ण। ➢ नैनीताल, हल्द्वानी, रूद्रपुर, काशीपुर, देहरादून, हरिद्वार, रूड़की के लिए मास्टर प्लान तैयार किये जाने हेतु जी0आई0एस0 मैपिंग का काम प्रगति पर है।	➢ जलापूर्ति सेक्टर 47 योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जायेगा। ➢ सीवरेज सेक्टर 44 योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जायेगा। ➢ ड्रेनेज सेक्टर 12 योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जायेगा। ➢ ग्रीन स्पेस/पार्क सेक्टर 44 योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जायेगा। ➢ नैनीताल, हल्द्वानी, रूद्रपुर, काशीपुर, देहरादून, हरिद्वार, रूड़की के लिए मास्टर प्लान तैयार किये जाने हेतु जी0आई0एस0 मैपिंग कार्य पूर्ण करना	➢ लोगों को यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार को निश्चित जलापूर्ति व सीवरेज कनैक्शन सहित नल सुलभ है। ➢ बाढ़ को कम करने और समाप्त करने के उद्देश्य से नालों व वर्षा जन नालों का निर्माण और सुधार। ➢ हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान (अर्थात पार्क) विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्धि करना। ➢ जी0आई0एस0 मैपिंग के फलस्वरूप अमृत शहरों के अन्तर्गत विकास कार्यों के लिए परियोजना तैयार करने में सुविधा होगी।
		1–26843 व्यक्तिगत शौचालय पूर्ण निर्मित। 2–2231 सीट के	1–27640 व्यक्तिगत शौचालय पूर्ण निर्मित । 2–2798 सीट के	1– 41 निकायों में ठोस अपषिष्ट प्रबन्धन का कार्य पूर्ण कराया जाना ।	➢ .जिन घरों में शौचालय नहीं थे उन घरों में शौचालय का निर्माण। ➢ नगरों में खुले में शौच की प्रवृत्ति का उन्मूलन।

क्र0 सं0	एस०डी० जी० Goals / Indicators	01–04–2023 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31–03–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2024–25
		सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालय पूर्ण। 3–698 सीट के सार्वजनिक मूत्रालय पूर्ण निर्मित। 4- कुल 1152 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा एकत्र किया जा रहा है।	सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालय पूर्ण । 3–1000 सीट के सार्वजनिक मूत्रालय पूर्ण निर्मित । 4- कुल 1242 वार्डों में से घर–घर कूड़ा एकत्रण तथा 1200 वार्डो में Source Segregation ।		➢ नगरों में स्वच्छता और सफाई की सुनिश्चिता। ➢ ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक रूप से निस्तारण।
3	11 Sustainable cities and communities	नगर निकाय दिनेशपुर तथा कर्णप्रयाग में 02 पार्क का निर्माण	20 नगर निकायों में ओपन जिम एवं पार्क निर्माण	समस्त 30 नगर निकायों में ओपन जिम एवं पार्क का निर्माण / सौन्दर्यकरण कराया जायेगा ।	नगरों को सुन्दर बनाने एवं नगर निकायों में एक बार पार्को के निर्माण तथा वर्तमान में स्थित पार्को का सुदृढ़ीकरण।
		नगर निगम, देहरादून, हल्द्वानी, काशीपुर रूद्रपुर हरिद्वार नगर पालिका परिषद, मंसूरी एवं नैनीताल, पिथौरागढ में ए0बी0सी0 कैम्पस की स्थापना व संचालन। नगर निकाय देहरादून, नैनीताल ,मसूरी में 64795 श्वान पशुओं की बाध्यकरण शल्य चिकित्सा पूर्ण कर ली गई है	➢ नैनीताल, मसूरी, देहरादून हल्द्वानी पिथौरागढ, अल्मोडा, हर्बटपुर, विकासनगर, सेलाकुई, डोईवाला, भीमताल, भवाली में बध्याकरण का संचालन किया जा रहा है। ➢ वर्तमान तक कुल 75000 पशुओं का बाध्यकरण शल्य चिकित्सा पूर्ण। ➢ रूद्रपुर, रूड़की, काशीपुर अल्मोडा में ए0बी0सी0 कैम्पस का निर्माण कार्य प्रगति पर है।	➢ रूद्रपुर, रूड़की, अल्मोडा में ए0बी0सी0 कैम्पस का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। ➢ आवारा पशुओं का बाध्य चिकित्सा की जायेगी।	ए0बी0सी0 कैम्पस की स्थापना के उपरान्त निकाय क्षेत्र में आवारा घूम रहे श्वान पशुओं की जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण सम्भव हो सकेगा।
		वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 में 03 निकायों क्रमषः कोटद्वार, अल्मोड़ा तथा हरिद्वार में निर्माण कार्य प्रगति पर है।	वित्तीय वर्ष 2021–22 एवं वित्तीय वर्ष 2022–23 में 03 निकायों क्रमषः कोटद्वार, अल्मोड़ा तथा हरिद्वार में निर्माण कार्य पूर्ण किये जायेगें।	08 नगर निकाय ऋषिकेष, गरूड़ कपकोट तथा बड़कोट में आश्रयहीन लोगों को रैनबसेरा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।	शहरी क्षेत्रों में आश्रयहीन गरीब लोगों को रात्रि विश्राम, ठहरने हेतु स्थान उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें शौचालय, बिस्तर, पानी आदि की निःशुल्क व्यवस्था होती है।

क्र0 सं0	एस०डी० जी० Goals / Indicators	01–04–2023 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31–03–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2024–25
		भारत सरकार के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य में ADB के सहयोग से 02 षहरों (देहरादून एवं नैनीताल) में नगरीय अवस्थापना जैसे सीवरेज, वॉटर सप्लाई का सुदृढ़ीकरण व विकास कार्य प्रगति पर है। ● वाटर सप्लाई –74 कि.मी. ● सीवर –185 कि.मी. ● एस0टी0पी0–कार्य प्रगति पर है। ● सीवर कनैक्शन–16385 नग। DEA भारत सरकार, ADB एवं शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा त्रिपक्षीय अनुबंध दिनांक 07.12.2021 को हस्ताक्षरित किया जा चुका है। देहरादून एवं नैनीताल नगर में 06 सब प्रोजेक्ट्स हेतु पेयजल, सीवरेज, ड्रैनेज एवं बरसाती जल प्रबन्धन आदि कार्य प्रगति पर हैं।	लगभग रू0 801.20 करोड़ की लागत से देहरादून तथा नैनीताल नगर में पेयजल, सीवरेज, ड्रैनेज एवं बरसाती जल प्रबन्धन आदि कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। DEA भारत सरकार ADB एवं शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा त्रिपक्षीय अनुबंध दिनांक 07.12.2021 को हस्ताक्षरित किया जा चुका है। देहरादून एवं नैनीताल नगर में 06 सब प्रोजेक्ट्स हेतु पेयजल, सीवरेज, ड्रैनेज एवं बरसाती जल प्रबन्धन आदि कार्य प्रगति पर हैं एवं नवीन पैकज हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।	देहरादून एवं नैनीताल में पेयजल अपव्यय तथा क्षरण में कमी किए जाने हेतु पेयजल सम्बन्धित कार्य किए जायेंगे। सीवरेज सम्बन्धित विकास कार्य किए जायेंगे। परियोजना के अन्तर्गत माह अक्टूबर–2023 तक ए0डी0बी को रू0 211.79 करोड़ के प्रतिपूर्ति दावे प्रेषित किये जा चुके है जिसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार से राज्य सरकार को कर दी गयी है। वर्तमान में परियोजना के अन्तगर्त वित्तीय वर्ष 2024–25 में ए0डी0बी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण किये जाने एवं परियोजना के अन्तर्गत देहरादून में डिफेंस कालोनी, नत्थनपुर, मोहकमपुर एवं नवादा में सीवरेज कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है। जिसके सापेक्ष अनुबंध उपरान्त 10 प्रतिशत मोबिलाइजेशन अग्रिम का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है इस प्रकार निर्माण कार्य हेतु पूंजीगत मद में रू 255.00 करोड़ एवं राजस्व मद में कार्यालय व्यय/अधिष्ठान एवं डी0एस0सी व्यय हेतु रू 25.00 करोड का व्यय किये जाने का अनुमान है।	उत्तराखण्ड के शहरी क्षेत्रों में स्थायी, सक्षम और उत्तरदायी सेवाओं के प्रतिपादन हेतु कार्य किया जाना, पर्यावरणीय स्थिरता को आसान बनाना इस परियोजना का समग्र उद्देश्य है। तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण विकास कार्यों में आने वाले अंतरालों की पहचान कर पहले से तैयार सभी बुनियादी अवस्थापनों को एकीकृत किया जाना। आधारभूत प्राथमिक शहरी सेवाओं (24x7) पेयजल, जल–मल प्रबंधन, बरसाती जल प्रबंधन, शहरी सड़क आदि) में शहरी जीवनशैली के स्तर अनुसार गुणवत्तापूर्ण सुधार। निकट भविष्य में नगरीय जनसंख्या के दबाव सहने योग्य तथा आकांक्षाओं पर खरा उतरने हेतु, सभी पर्याप्त सुविधाओं से सुसज्जित, सुनियोजित तंत्र का निर्माण करना।

क्र0 सं0	एस०डी० जी० Goals / Indicators	01–04–2023 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31–03–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2024–25
		बाह्य सहायतित योजना–2 परियोजना US$ 250 मीलियन (रू 2000 करोड) अनुमानित लागत की है जिसमें वित्त पोषित एव राज्य का 80:20 का अंश है। जिसके अन्तर्गत टेण्डर प्रक्रिया गतिमान है।	प्रथम चरण में चार जिलों (नैनीताल, देहरादून, पौडी, उधम सिंह नगर) के पांच नगर निकायों (हल्द्वानी, विकासनगर, चंपावत, कोटद्वार एवं किच्छा) हेतु टेण्डर प्रक्रिया गतिमान है।	प्रथम चरण में चार जिलों (नैनीताल, देहरादून, पौडी, उधम सिंह नगर) के पांच नगर निकायों (हल्द्वानी, विकासनगर, चंपावत, कोटद्वार एवं किच्छा) में 24X7 पेयजल, अपशिष्ट जल प्रबन्धन, बरसाती जल प्रबन्धन, प्रशासनिक भवन, शहरी सड़कें, यातायात और पार्किंग, वैंडिंग जोन, सूचना संपर्क तकनीकी और ओपन स्पेस जैसे कार्य किए जायेंगे। वित्तीय वर्ष 2024–25 में पैकजों के अनुबन्ध उपरान्त मोबिलाईजेशन एडवान्स एव पैकजो के भुगतान हेतु पूंजीगत मद में रू0 109.00 करोड़ एवं राजस्व मद में डी0एस0सी0/सर्वे इत्यादि व्यय हेतु रू0 10.00 करोड का व्यय किये जाने का अनुमान है।	परियोजना के अन्तर्गत नगरों में स्वचालित स्काडा तकनीक के द्वारा चौबीस घंटे पानी की सुविधा प्राप्त होगी, घरों में पेयजल मीटर लगाये जायेंगे ताकि पानी के अपव्यय को कम किया जा सके। सुरक्षित, स्वस्छ और स्वस्थ पर्यावरणीय परिस्थितियों को बनाये रखने हेतु अपशिष्ट जल प्रबन्धन किया जायेगा। बरसाती पानी के प्रबन्धन हेतु विकास कार्य किये जायेंगे। वहीं सड़कों व पार्किंग का निर्माण कर यातायात प्रबन्धन का कार्य भी किया जायेगा। छोटे फुटकर व्यापारियों हेतु वैन्डिंग जोन का निर्माण किया जायेगा। नियमित स्थानीय निकाय सुदृढ़ीकरण तथा सशक्तिकरण हेतु सूचना संचार तकनीकी का उपयोग किया जायेगा। इन सभी अवस्थापना विकास कार्यों के फलस्वरूप नगरीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा तथा नागरिक विकास स्तर भी सुदृढ़ होगा।
		जलापूर्ति (लक्ष्य–47 योजना) के सापेक्ष 10 योजनाएं पूर्ण, 37 योजनाओं कार्य प्रगति पर। सीवरेज (लक्ष्य–44 योजना) के सापेक्ष 25 योजनाएं पूर्ण, 19 योजनाओं कार्य प्रगति पर। ड्रेनेज (लक्ष्य–16) 6 पूर्ण, 10 योजनाओं का कार्य प्रगति पर। ग्रीनस्पेस/पार्क (लक्ष्य–44) के सापेक्ष 24 योजनाए पूर्ण, 20 योजनाओं का कार्य प्रगतिपर।	➢ जलापूर्ति (लक्ष्य–47 योजना) के सापेक्ष 44 योजनाएं पूर्ण। ➢ सीवरेज (लक्ष्य–44 योजना) के सापेक्ष 43 योजनाएं पूर्ण। ➢ ड्रेनेज सेक्टर (लक्ष्य–16) 15 योजनाएं पूर्ण। ➢ ग्रीन स्पेस/पार्क सेक्टर (लक्ष्य–44) के सापेक्ष 42 योजनाएं पूर्ण। ➢ नैनीताल, हल्द्वानी, रूद्रपुर, काशीपुर, देहरादून, हरिद्वार, रूड़की के लिए मास्टर प्लान तैयार किये जाने हेतु जी0आई0एस0 मैपिंग का काम प्रगति पर है।	➢ जलापूर्ति सेक्टर 47 योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जायेगा। ➢ सीवरेज सेक्टर 44 योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जायेगा। ➢ ड्रेनेज सेक्टर 12 योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जायेगा। ➢ ग्रीन स्पेस/पार्क सेक्टर 44 योजनाओं का कार्य पूर्ण किया जायेगा। ➢ नैनीताल, हल्द्वानी, रूद्रपुर, काशीपुर, देहरादून, हरिद्वार, रूड़की के लिए मास्टर प्लान तैयार किये जाने हेतु जी0आई0एस0 मैपिंग कार्य पूर्ण करना	➢ लागों को यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक परिवार को निश्चित जलापूर्ति व सीवरेज कनैक्शन सहित नल सुलभ है। ➢ बाढ़ को कम करने और समाप्त करने के उद्देश्य से नालों व वर्षा जन नालों का निर्माण और सुधार। ➢ हरित क्षेत्र और सुव्यवस्थित खुले मैदान (अर्थात पार्क) विकसित करके शहरों की भव्यता में वृद्धि करना। ➢ जी0आई0एस0 मैपिंग के फलस्वरूप अमृत शहरों के अन्तर्गत विकास कार्यों के लिए परियोजना तैयार करने में सुविधा होगी।
		1–26843 व्यक्तिगत शौचालय पूर्ण निर्मित। 2–2231 सीट के	1–27640 व्यक्तिगत शौचालय पूर्ण निर्मित । 2–2798 सीट के	1– 41 निकायों में ठोस अपषिष्ट प्रबन्धन का कार्य पूर्ण कराया जाना ।	➢ .जिन घरों में शौचालय नहीं थे उन घरों में शौचालय का निर्माण। ➢ नगरों में खुले में शौच की प्रवृत्ति का उन्मूलन।

क्र0 सं0	एस०डी० जी० Goals / Indicators	01–04–2023 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31–03–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2024–25
		सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालय पूर्ण। 3–698 सीट के सार्वजनिक मूत्रालय पूर्ण निर्मित। 4- कुल 1152 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा एकत्र किया जा रहा है।	सामुदायिक / सार्वजनिक शौचालय पूर्ण । 3–1000 सीट के सार्वजनिक मूत्रालय पूर्ण निर्मित । 4- कुल 1242 वार्डों में से घर–घर कूड़ा एकत्रण तथा 1200 वार्डो में Source Segregation ।		➢ नगरों में स्वच्छता और सफाई की सुनिश्चिता। ➢ ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक रूप से निस्तारण।
		प्रधानमंत्री आवास योजनार्न्तगत 7640 आवास पूर्ण किये गये है तथा 8105 मकान का काम प्रगति पर है ।	➢ योजनान्तर्गत लाभार्थी आधारित घटक अंतर्गत 316 परियोजनाओं में 25760 आवास स्वीकृत 16378 आवासों पर कार्य प्रगति पर जिनमें से 11860 आवास पूर्ण होने सम्भावित है। ➢ भागीदारी में **किफायती आवास घटक अंतर्गत 20 परियोजनाओं में 15960 आवास स्वीकृत 1344 पर कार्य पूर्ण तथा 14616 आवासों पर कार्य प्रगति पर।**	➢ योजनान्तर्गत लाभार्थी आधारित घटक अंतर्गत 1200 आवास को पूर्ण करा लिया जायेगा। ➢ भागीदारी में किफायती आवास घटक अंतर्गत 2152 आवासों को पूर्ण कराने लक्षित है।	➢ इस परियोजना के अन्तर्गत आवासों का निर्माण करते हुए शहरी क्षेत्र में लोगों को अपना आवास तथा बुनियादी अवस्थापना सुविधाएं जैसेः– बेहतर समेकित विकास, जलापूर्ति–सफाई सुविधा, आदि उपलब्ध होगी।
		–परियोजना के अन्तर्गत इन्ट्रीग्रेटेड कमांड कन्ट्रोल का कार्य, परेड ग्राउंड कायाकल्प, पल्टन बाजार, वाटर ए0टी0एम0, क्रेच बिल्डिंग, स्मार्ट टायलेट, स्मार्ट स्कूल, मॉडर्न दून लाईब्रेरी, इलैक्ट्रिक बस, स्मार्ट वॉटर मैनेजमेंट निर्माण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। –परियोजना के अन्तर्गत स्मार्ट रोड, इंटीग्रेटेड ड्रेनेज सिस्टम का निर्माण कार्य प्रारम्भ। –इंटीग्रेटेड ऑफिस काम्पलेक्स ग्रीन बिल्डिंग का निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2024–25 में प्रारम्भ किया जाएगा।	➢ इंटीग्रेटेड ड्रेनेज सिस्टम का कार्य 30 मार्च 2024 तक पूर्ण हो जाएगा। ➢ इंटीग्रेटेड सीवेरज का कार्य 30 मार्च 2024 तक पूर्ण हो जाएगा। ➢ स्मार्ट रोड़ का कार्य 30 मार्च 2024 तक पूर्ण हो जाएगा।	➢ वर्तमान में शहर के विभिन्न स्थानों में वर्षा के दौरान जल भराव की समस्या उत्पन्न हो जाती है। जिसके लिए एक बेहतर ड्रेनेज सिस्टम प्रस्तावित किया गया है। ➢ ए0बी0डी0 एरिया में सीवर लाइन काफी पुरानी है और उसे बदले जाने का प्रस्ताव है। जिससे शहर में सीवरेज लाइन समस्या का निस्तारण किया जयेगा। ➢ स्मार्ट रोड के कार्य में सड़कों के दोनों ओर डक्ट बनाई जायेगी जिसमें बिजली, पानी की लाईन	➢ देहरादून नगर का सुनियोजित विकास होगा जिससे बेहतर पेयजल व्यवस्था सीवरेज, यातायात की सुविधा निवासियों को उपलब्ध होगी। ➢ इंटीग्रेटेड ऑफिस काम्पलेक्स ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण से आम जनता को एक ही स्थान पर समस्त कार्यालय की सुविधा उपलब्ध होगी।

क्र0 सं0	एस०डी० जी० Goals / Indicators	01–04–2023 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31–03–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2024–25
				डाली जायेगी जिससे तारो का जाल हट जयेगा साथ ही सड़को पर बेतरतीब खड़ें बिजली के खम्बो के हटने से भी यातायात संचालन में सुविधा रहेगी। उक्त कार्य मार्च 2024 तक समाप्त कर दिया जायेगा। ➢ ग्रीन बिल्डिंग में 73 सरकारी विभागों को स्थान्तरित किया जा रहा है जिससे आम जनता को एक ही स्थान पर सभी कार्यालय होने से लाभ प्राप्त होगा तथा कार्य सितम्बर, 2026 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।	
4	12 sustainable construction and production	प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत 7640 आवास पूर्ण किये गये है तथा 8105 मकान का काम प्रगति पर है ।	➢ योजनान्तर्गत लाभार्थी आधारित घटक अंतर्गत 316 परियोजनाओं में 25760 आवास स्वीकृत 16378 आवासों पर कार्य प्रगति पर जिनमें से 11860 आवास पूर्ण होने सम्भावित है। ➢ भागीदारी में किफायती आवास घटक अंतर्गत 20 परियोजनाओं में 15960 आवास स्वीकृत 1344 पर कार्य पूर्ण तथा 14616 आवासों पर कार्य प्रगति पर।	➢ योजनान्तर्गत लाभार्थी आधारित घटक अंतर्गत 4518 आवास को पूर्ण करा लिया जायेगा। ➢ भागीदारी में किफायती आवास घटक अंतर्गत 14616 आवासों को पूर्ण कराने लक्षित है।	➢ इस परियोजना के अन्तर्गत आवासों का निर्माण करते हुए शहरी क्षेत्र में लोगों को अपना आवास तथा बुनियादी अवस्थापना सुविधाएं जैसेः– बेहतर समेकित विकास, जलापूर्ति–सफाई सुविधा, आदि उपलब्ध होगी।
		कुल 1152 वार्डों में डोर टू डोर कूड़ा एकत्र किया जा रहा है।	कुल 1242 वार्डों में से घर–घर कूड़ा एकत्रण तथा 1200 वार्डो में Source Segregation ।	41 निकायों में ठोस अपषिष्ट प्रबन्धन का कार्य पूर्ण कराया जाना ।	➢ नगरों में स्वच्छता और सफाई की सुनिश्चिता। ➢ ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक रूप से निस्तारण।
		भारत सरकार के माध्यम से उत्तराखण्ड राज्य में ADB के सहयोग से 02 शहरों	लगभग रू0 801.20 करोड़ की लागत से देहरादून तथा नैनीताल	देहरादून एवं नैनीताल में पेयजल अपव्यय तथा क्षरण में कमी किए जाने	उत्तराखण्ड के शहरी क्षेत्रों में स्थायी, सक्षम और उत्तरदायी सेवाओं के प्रतिपादन हेतु कार्य किया

क्र0 सं0	एस०डी० जी० Goals / Indicators	01–04–2023 की स्थिति (भौतिक स्थिति)	31–03–2024 की सम्भावित स्थिति (भौतिक)	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटपुट वर्ष 2024–25	परिकल्पित (प्रोजेक्टेड) आउटकम 2024–25
		(देहरादून एवं नैनीताल) में नगरीय अवस्थापना जैसे सीवरेज, वॉटर सप्लाई का सुदृढ़ीकरण व विकास कार्य प्रगति पर है। ● वाटर सप्लाई –74 कि.मी. ● सीवर –185 कि.मी. ● एस0टी0पी0–कार्य प्रगति पर है। ● सीवर कनैक्शन–16385 नग। DEA भारत सरकार, ADB एवं शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा त्रिपक्षीय अनुबंध दिनांक 07.12.2021 को हस्ताक्षरित किया जा चुका है। देहरादून एवं नैनीताल नगर में 06 सब प्रोजेक्ट्स हेतु पेयजल, सीवरेज, ड्रैनेज एवं बरसाती जल प्रबन्धन आदि कार्य प्रगति पर हैं।	नगर में पेयजल, सीवरेज, ड्रैनेज एवं बरसाती जल प्रबन्धन आदि कार्य सम्पादित किये जा रहे हैं। DEA भारत सरकार ADB एवं शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा त्रिपक्षीय अनुबंध दिनांक 07.12.2021 को हस्ताक्षरित किया जा चुका है। देहरादून एवं नैनीताल नगर में 06 सब प्रोजेक्ट्स हेतु पेयजल, सीवरेज, ड्रैनेज एवं बरसाती जल प्रबन्धन आदि कार्य प्रगति पर हैं एवं नवीन पैकज हेतु निविदा आमंत्रित की जा चुकी है।	हेतु पेयजल सम्बन्धित कार्य किए जायेंगे। सीवरेज सम्बन्धित विकास कार्य किए जायेंगे। परियोजना के अन्तर्गत माह अक्टूबर–2023 तक ए0डी0बी को रू0 211.79 करोड़ के प्रतिपूर्ति दावे प्रेषित किये जा चुके है जिसकी प्रतिपूर्ति भारत सरकार से राज्य सरकार को कर दी गयी है। वर्तमान में परियोजना के अन्तगर्त वित्तीय वर्ष 2024–25 में ए0डी0बी द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ण किये जाने एवं परियोजना के अन्तर्गत देहरादून में डिफेंस कालोनी, नत्थनपुर, मोहकमपुर एवं नवादा में सीवरेज कार्य हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है। जिसके सापेक्ष अनुबंध उपरान्त 10 प्रतिशत मोबिलाइजेशन अग्रिम का भुगतान किया जाना प्रस्तावित है इस प्रकार निर्माण कार्य हेतु पूंजीगत मद में रू 255.00 करोड़ एवं राजस्व मद में कार्यालय व्यय/अधिष्ठान एवं डी0एस0सी व्यय हेतु रू 25.00 करोड का व्यय किये जाने का अनुमान है।	जाना, पर्यावरणीय स्थिरता को आसान बनाना इस परियोजना का समग्र उद्देश्य है। तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण विकास कार्यों में आने वाले अंतरालों की पहचान कर पहले से तैयार सभी बुनियादी अवस्थापनों को एकीकृत किया जाना। आधारभूत प्राथमिक शहरी सेवाओं (24x7) पेयजल, जल–मल प्रबंधन, बरसाती जल प्रबंधन, शहरी सड़क आदि) में शहरी जीवनशैली के स्तर अनुसार गुणवत्तापूर्ण सुधार। निकट भविष्य में नगरीय जनसंख्या के दबाव सहने योग्य तथा आकांक्षाओं पर खरा उतरने हेतु, सभी पर्याप्त सुविधाओं से सुसज्जित, सुनियोजित तंत्र का निर्माण करना।

1–दीन दयाल अत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन– शहरी विकास अन्तर्गत दीन दयाल अत्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे0–एन0यू0एल0एम0) के अन्तर्गत आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में Spark Ranking में उत्तराखण्ड राज्य ने पूरे भारत वर्ष में तृतीय स्थान प्राप्त किया।

2–प्रधानमंत्री आवास योजना(शहरी)– आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अन्तर्गत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली निकायों में नगर पंचायत श्रेणी में देवप्रयाग नगर पंचायत ने तृतीय स्थान प्राप्त किया।

3–स्वच्छ भारत मिशन(शहरी)– योजनान्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण–2023 के अन्तर्गत 01 लाख से अधिक जनसंख्या की श्रेणी में नगर निगम देहरादून को एवं 01 लाख से कम जनसंख्या की श्रेणी में नगर पालिका परिषद मुनिकीरेती को भारत सरकार द्वारा Clean City पुरस्कार से सम्मानित किया गया।